33 घंटे तक चली सर्जरी के जरिये सिर से जुड़ी बांग्लादेश की तीन साल की जुड़वा बहनों रबिया और रुकिया को चिकित्सकों की टीम ने अलग कर लिया है। हंगरी से आए 30 डॉक्टरों और स्थानीय चिकित्सकों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को यहां एक सैन्य अस्पताल में अंजाम दिया।

सऊदी महिलाओं को अकेले विदेश जाने की मिली आजादी

नए नियमों का हुआ एलान, पुरुषों की अनुमति के बिना पा सकेंगी पासपोर्ट

न्यूयॉर्क टाइम्स से

रियाद : छवि सुधारने में जुटे सऊदी अरब ने महिलाओं को अकेले विदेश जाने की छूट दे दी है। वे अब पुरुष रिश्तेदार के बगैर विदेश में काम भी कर सकेंगी। महिलाओं के अकेले विदेश जाने पर लगे प्रतिबंध के कारण सऊदी सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह की बंदिशों को महिलाओं के अधिकारों का दमन करार दिया था।

सऊदी सरकार ने शुक्रवार को नए नियमों का एलान किया। इनके तहत वयस्क महिलाओं को पुरुषों की इजाजत के बिना पासपोर्ट पाने, विदेश जाने और काम करने की अनुमति होगी। पहले महिलाओं को पासपोर्ट पाने के लिए आमतौर पर पिता या पति की अनुमति की जरूरत पड़ती थी। कई बार तो उन्हें पासपोर्ट पाने, विदेश जाने, नौकरी करने या चिकित्सा संबंधी यात्रा करने के लिए अपने बेटे या किसी दूसरे पुरुष रिश्तेदारों की भी इजाजत लेनी पड़ती थी। इस तरह की तमाम बंदिशों समेत पुरुषों की प्रताड़ना और भेदभावपूर्ण कानून व्यवस्था से तंग होकर हाल के वर्षों में कई सऊदी महिलाएं विदेश भाग गईं। उनका कहना था कि सऊदी की कानून व्यवस्था उनकी रक्षा नहीं करती। इस साल जनवरी में रहाफ मुहम्मद अलकुनान नामक 18 साल की युवती सऊदी अरब से भागकर थाइलैंड पहुंच गई थी। सोशल मीडिया के जरिये उसने खुद पर ढाए अपने परिवार के जुल्मों को बयां किया था।

सऊदी अरब में अभी तक महिलाओं को विदेश जाने के लिए अपने पिता या पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन, क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने इन दिनों सामाजिक सुधारों की मुहिम छेड़ रखी है। इसी का परिणाम है कि अब यहां महिलाएं स्वेच्छा से विदेश जा सकेंगी। फाइल फोटो, एएफपी

मुल्क की छवि सुधारने में जुटे हैं क्राउन प्रिंस : सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे बंदिशों वाले स्थान के तौर पर बनी अपने मुल्क की छवि को सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। इसी कवायद में यह नया कदम उठाया गया है। वह 2015 से ही सामाजिक सुधार की मुहिम में जुटे हैं। महिलाओं पर बंदिशें लगाने वाले नियमों के बारे में पिछले साल क्राउन प्रिंस ने कहा था कि वह इन्हें समाप्त करना पसंद करेंगे।

पिछले साल मिली ड्राइविंग की छूट : क्राउन प्रिंस सलमान के प्रयास से ही पिछले साल महिलाओं को ड्राइविंग की छूट मिली थी। यह अधिकार पाने के लिए सऊदी महिलाएं लंबे समय से मांग कर रही थीं। 1990 में पहली बार इसके लिए मुहिम शुरू हुई थी।

चर्चित केनेडी परिवार में दवाओं की ओवरडोज से एक की मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में शुमार केनेडी परिवार में फिर एक हादसा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के भाई रॉबर्ट एफ केनेडी की पोती साओर्स केनेडी हिल (22) की गुरुवार को कथित तौर पर दवाओं के ओवरडोज से मौत हो गई। न्यूयॉर्क से सीनेटर रहे रॉबर्ट अमेरिका के अटॉर्नी जनरल भी रहे थे।

केनेडी परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, साओर्स अपनी दादी इथेल (91) के साथ मैसाच्युसेट्स स्थित पैतृक आवास केनेडी कंपाउंड में थीं। गुरुवार दोपहर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत केप कोड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पॉल माइकल हिल और कर्टनी केनेडी हिल की इकलौती संतान साओर्स बोस्टन कॉलेज में पढ़ती थीं। 2016 में उन्होंने खुद के डिप्रेशन और मानसिक रोग से पीड़ित होने की जानकारी भी दी थी। केनेडी परिवार ने साओर्स की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। दादी इथेल ने कहा, 'साओर्स के चले जाने से यह दुनिया आज कम खूबसूरत लग रही है।'

अमेरिका और रूस की ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि खत्म

वाशिंगटन में 8 दिसंबर 1987 को अमेरिका और सोवियत के बीच हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि के दौरान हाथ मिलाते तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (दाएं) और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव। हथियारों के विकास की होड़ रोकने के लिए तीन दशक पहले हुई इस संधि से शुक्रवार को रूस ने खुद को अलग कर लिया है। फाइल फोटो, एपी

- दुनिया में शुरू हो सकती है नए हथियारों के विकास की होड़

वाशिंगटन, एपी : परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तीन दशक पहले हुई ऐतिहासिक संधि शुक्रवार को खत्म हो गई। दोनों देशों के बीच 1987 में हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) संधि के खत्म होने से दुनिया में नए हथियारों के विकास की होड़ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने शुक्रवार को थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक क्षेत्रीय सम्मेलन में आइएनएफ संधि से अमेरिका के हटने का औपचारिक एलान किया। इसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर संधि खत्म होने का एलान कर दिया। अमेरिका ने संधि खत्म होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि रूस सालों से ऐसे हथियार विकसित कर रहा है, जो इस संधि का उल्लंघन है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों खासतौर पर यूरोप को खतरा पैदा हो गया है। इस आरोप से इन्कार करते हुए रूस ने कहा कि अमेरिका नई मिसाइलें विकसित करने के लिए संधि से हटने का बहाना बना रहा था।

ट्रंप ने अक्टूबर में किया था एलान : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 20 अक्टूबर को यह एलान किया था कि वह इस संधि से अमेरिका को अलग कर रहे हैं। अमेरिका ने गत एक फरवरी को आइएनएफ संधि को निलंबित कर दिया था। इसके बाद रूस ने भी संधि को निलंबित कर दिया था। अब दोनों देश औपचारिक तौर पर इस संधि से अलग हो गए।

मध्यम दूरी की मिसाइलें की गई थीं प्रतिबंधित : आइएनएफ संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाच्योव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत मध्यम दूरी यानी 5,500 किलोमीटर तक मार करने वाली कई मिसाइलों को प्रतिबंधित किया गया था।

त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण समझौते के इच्छुक ट्रंप : ट्रंप प्रशासन का दावा है कि चीन परमाणु हथियारों के अपने जखीरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में उसे परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर नहीं रखा जा सकता। ट्रंप इस बात की इच्छा जता चुके हैं कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हो।

न्यू स्टार्ट समझौता भी खतरे में : ट्रंप प्रशासन रूस के साथ 2010 में हुए न्यू स्टार्ट समझौते को भी आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं दिख रहा। इस समझौते की अवधि 2021 में खत्म होने वाली है। इस समझौते के तहत परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट को ही नवीनीकृत करने का सुझाव दिया था। लेकिन ट्रंप नए सिरे से संधि करने पर अड़े हैं। उन्होंने न्यू स्टार्ट को खराब समझौता करार देते हुए कहा था कि इसे ओबामा प्रशासन ने किया था।

नाटो ने रूस को ठहराया जिम्मेदार

ब्रसेल्स, एएफपी : 29 देशों के गुट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन (नाटो) ने आइएनएफ संधि खत्म होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। नाटो ने कहा, 'हमें खेद है कि रूस ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर लौटने की कोई स्पष्ट इच्छा नहीं दिखाई।'

कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान से होगी बात : जयशंकर

सुर बदले ▶ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों पक्ष करें आग्रह तो करेंगे मध्यस्थता

बैंकाक में हुई अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ से जयशंकर की मुलाकात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत ने अमेरिका को दो टूक कहा है कि वह कश्मीर को लेकर किसी भी सूरत में मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं जा रहा। कश्मीर पर पाकिस्तान के सिवाय और किसी भी देश से बात करने का सवाल नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोंपिओ को भारतीय नीति से अवगत कराया। वैसे जयशंकर यह बात संसद में पहले ही कह चुके हैं। यह बैठक बैंकाक में हुई जहां दोनों नेता पूर्वी एशिया समूह के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। भारत के इस कड़े रुख का असर अमेरिका पर भी पड़ता दिख रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदलने के संकेत हैं। उन्होंने कश्मीर में तभी मध्यस्थता करने की बात कही है जब इसका आग्रह दोनों पक्षों से आए।

पोंपिओ से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने जो ट्वीट किए हैं उससे साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए जो बयानबाजी की गई थी उसको लेकर भारत कितना गंभीर है। जयशंकर ने कहा, 'मैंने अपने समकक्ष पोंपिओ को साफ शब्दों में बता दिया है कि कश्मीर पर अगर कोई बात होगी तो वह सिर्फ पाकिस्तान से होगी और वह भी द्विपक्षीय तौर पर।'

थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में शुक्रवार को आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के बीच मुलाकात हुई। एएनआइ

ट्रंप ने पिछले दिनों पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का वाशिंगटन में स्वागत करते हुए बयान दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार भी है। भारत में ट्रंप के इस बयान को काफी राजनीतिक रंग दिया गया। कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राजग सरकार कश्मीर पर भारत की पारंपरिक नीति का त्याग कर रही है। सरकार ने इसका पुरजोर खंडन भी किया। अब गुरुवार को वाशिंगटन में ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता को लेकर जो नया बयान दिया है उससे लगता है कि अमेरिका भारत की नाराजगी से सतर्क हो गया है। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि भारत तो आपकी मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा तो अब आप क्या करेंगे, इसका जवाब उन्होंने दिया कि, 'यह पीएम मोदी पर ही निर्भर करता है कि वह हमारा सुझाव स्वीकार करते हैं या नहीं। मोदी और खान (पाकिस्तान पीएम इमरान खान) दोनों बेहद शानदार आदमी हैं। मुझे लगता है कि दोनों के बीच अच्छी बात हो सकती है लेकिन अगर वे चाहते हैं कि कोई मध्यस्थता करे तो हम कर सकते हैं।'

पाक को सैन्य मदद देने पर भारत ने अमेरिका से जताया विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के अमेरिका के फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यहां अमेरिकी राजदूत और वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने कहा, 'हमने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के साथ ही वाशिंगटन में हमारे राजदूत के जरिये अमेरिकी सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया है। हमने पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा सैन्य सहायता देने पर गंभीर चिंता जताई है।'

सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी राजदूत को साउथ ब्लॉक बुलाया गया और पाकिस्तान सेना की मदद करने के अमेरिका के फैसले पर उनके समक्ष विरोध दर्ज कराया गया। पेंटागन ने पिछले सप्ताह अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को जानकारी दी थी कि उसने 12 करोड़ 50 लाख डॉलर (करीब 862 करोड़ रुपये) की सैन्य बिक्री की मंजूरी दी है, जिससे पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों की निगरानी की जाएगी। यह सूचना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच व्हाइट हाउस में बैठक के बाद दी गई। रवीश कुमार ने कहा, 'अमेरिका ने हमें बताया कि प्रस्तावित बिक्री से पाकिस्तान को सैन्य सहायता रोककर रखने की अमेरिका की नीति में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता।' उन्होंने कहा, 'अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि प्रस्तावित बिक्री का उद्देश्य अमेरिका को तकनीकी और साजो-सामान सेवाएं जारी रखने में सक्षम बनाना है ताकि पाकिस्तान की एफ-16 विमानों की इन्वेंट्री के संचालन की निगरानी में सहायता की जा सके।' पाक ने बालाकोट हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत के खिलाफ एफ-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था।

भारतवंशी डॉक्टर भाषा मुखर्जी बनीं मिस इंग्लैंड

लंदन, आइएएनएस : भारतवंशी डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने दर्जनों प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस इंग्लैंड का ताज अपने नाम कर लिया। डर्बी की रहने वाली 23 वर्षीय भाषा के पास स्नातक की दो डिग्री हैं। इस जीनियस सुंदरी का आइक्यू 146 है और वह पांच भाषाएं बोल सकती हैं। मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता खत्म होते ही वह बोस्टन स्थित हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के तौर पर नौकरी शुरू करने वाली थीं। अब वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी।

भारत में जन्मीं भाषा नौ साल की उम्र में अपने माता-पिता के साथ इंग्लैंड पहुंच गई थीं। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंस के साथ उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी में भी स्नातक किया है। मिस इंग्लैंड के आखिरी चरण से पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, 'कई लोग सोचते हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतने वाली लड़कियां बुद्धू होती हैं। लेकिन हम सब किसी ना किसी मकसद से ही यहां हैं। मेडिकल की पढ़ाई के बीच मैंने इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में सोचा। इसके लिए मुझे खुद को बहुत समझाना भी पड़ा था।' स्कूल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थीं इसलिए अपने शिक्षकों की चहेती थीं। क्लास में सबसे होशियार होने के लिए उन्हें आइंस्टीन अवार्ड भी मिला था। वह एक सामाजिक संस्था भी चलाती हैं।

पाक सेना की सफाई, सीनेट में नहीं गिराया अविश्वास प्रस्ताव

- अंतिम वक्त में कुछ सांसदों के पाला बदलने से गिरा विपक्ष का प्रस्ताव

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विपक्ष ने सेना पर संसद के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विफल कराने का आरोप लगा है। सेना ने हालांकि इससे इन्कार करते हुए शुक्रवार को कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने में खुफिया एजेंसी आइएसआइ की कोई भूमिका नहीं थी।

सीनेट अध्यक्ष संजरानी के खिलाफ गुरुवार को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वह गिर गया। संयुक्त विपक्ष अपनी जीत की उम्मीद लगाए था लेकिन उसका प्रस्ताव महज तीन वोटों से पारित होने से रह गया। प्रस्ताव को 50 सांसदों का समर्थन मिला। मतदान से आधे घंटे पहले सभी 64 विपक्षी सदस्य संजरानी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए थे। लेकिन गुप्त मतदान के दौरान 14 सांसदों ने पाला बदल लिया। विपक्षी सांसद और सीनेट अध्यक्ष के संयुक्त उम्मीदवार मीर हसिल खान ने इस हार के लिए इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आइएसआइ) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जिम्मेदार ठहराया।

अपनी हार का कारण पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया, 'वे जनरल फैज के लोग थे। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जानते हैं।' इस आरोप से इन्कार करते हुए सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट में कहा, 'मुल्क के प्रमुख संस्थान पर सांसद मीर हासिल के आरोप बेबुनियाद हैं। सियासी फायदे के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।' रक्षा मंत्री परवेज खटक ने भी सांसद मीर हसिल खान के बयान की निंदा की है।

आसिफ गफूर साभार : ट्विटर

पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ के दो भतीजों को विमान से उतारा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने हज यात्रा पर जा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दो भतीजों को विमान से उतार लिया। इमिग्रेशन अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के आग्रह पर यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज अब्बास को गुरुवार को लाहौर के अल्लामा इकबाल हवाई अड्डे से मदीना जाने को तैयार फ्लाइट से नीचे उतारा गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के देश छोड़कर जाने पर रोक लगी है।

चौधरी चीनी मिल कंपनी से जुड़े अरबों रुपये के भ्रष्टाचार मामले में शरीफ परिवार के अन्य सदस्यों की तरह यूसुफ और अब्दुल पर भी मनी लांड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच कर रही पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी एनएबी ने हाल में दोनों से इस कंपनी में हिस्सेदारी और मुनाफे को लेकर पूछताछ की थी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एनएबी ने गृह मंत्रालय से दोनों के नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट (पीएनआइएल) में डाल देने की सिफारिश की थी। इस सूची में शामिल लोगों के देश छोड़ने पर पाबंदी रहती है। मिल मामले में शरीफ की बेटी मरयम से भी पूछताछ की गई थी।

उपचुनाव में हार के बाद मुश्किल में फंस सकती है बोरिस जॉनसन सरकार

- उपचुनाव में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के प्रत्याशी क्रिस डेविस की हार
- जॉनसन के पास बचा 320 सांसदों का समर्थन, विपक्ष के पास 319 सीटें

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार को उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। वेल्स उपचुनाव में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के क्रिस डेविस की हार के बाद सरकार नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। टेरीजा मे के इस्तीफे के बाद पीएम बने जॉनसन संसद में अपना बहुमत गंवा सकते है। 650 सदस्यों वाली संसद में कंजरवेटिव पार्टी के 310 और डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी (डीयूपी) के 10 सदस्यों को मिलाकर जॉनसन के पास 320 सांसदों का समर्थन है। जबकि विपक्षी दलों के 319 सदस्य हैं।

वेल्स की ब्रेकन एंड रैडनोशायर सीट के लिए हुए उपचुनाव में लिबरल डेमोक्रेट नेता जेन डाड्स ने क्रिस को 1,425 वोटों से हराया। खर्च में गड़बड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद क्रिस को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद भी पार्टी ने उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया। यह चुनाव जॉनसन के लिए पहली चुनौती माना जा रहा था। यह पहली बार है जब किसी नए प्रधानमंत्री को पद संभालने के इतने कम दिनों में ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जीत के बाद डाड्स ने कहा, 'मेरा पहला काम जॉनसन को ढूंढकर उन्हें यह बताना है कि वह हमारे देश के भविष्य के साथ खेलना बंद करें।' दरअसल, जॉनसन ने 31 अक्टूबर तक बिना किसी समझौते के भी ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की बात की है। विपक्ष के साथ ही कंजरवेटिव पार्टी के कुछ सांसद भी इसके विरोध में है।

ब्रिटेन में हुए उपचुनाव में लिबरल डेमोक्रेट नेता जेन डाड्स ने सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के क्रिस डेविस को 1,425 वोटों से हराया। एएफपी

डाड्स की जीत से खुश लिबरल डेमोक्रेट नेता जो स्विंसन ने कहा, 'जॉनसन का घटता बहुमत इस बात का सुबूत है कि उनके पास ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकालने का समर्थन नहीं है।' लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह की मांग कर रही है।

तनाव के आसार

प्रशांत महासागर और रूस के ओखोस्क सागर को अलग करने वाले कुरील द्वीपसमूह के चारों द्वीप बने हुए हैं रूस और जापान के बीच विवाद का कारण

विवादित द्वीप पर पहुंचे रूसी पीएम, जापान नाराज

टोक्यो, रायटर : रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव शुक्रवार को विवादित कुरील द्वीपसमूह के एक द्वीप पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा से जापान और रूस के बीच फिर तनाव बढ़ने की आशंका है। जापान के विदेश मंत्रालय ने मेदवेदेव की इस यात्रा को खेदजनक बताया है। प्रशांत महासागर और रूस के ओखोस्क सागर को अलग करने वाले कुरील द्वीपसमूह के चारों द्वीप रूस और जापान के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान भी इन पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इसी के चलते दोनों देशों में अब तक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। मेदवेदेव की यात्रा पर एतराज जताते हुए जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'उनकी यात्रा जापान की संप्रभुता और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध बढ़ाने और शांति समझौते के लिए रूसी पक्ष ठोस कदम उठाए।' वर्ष 2015 के बाद मेदवेदेव पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे हैं। उनका यह कदम शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत और द्वीप पर हो रहे साझा आर्थिक कार्यक्रमों में बाधा बन सकता है।

रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने शुक्रवार को विवादित कुरील द्वीपसमूह के इतुरुप द्वीप का दौरा किया। जापान ने मेदवेदेव की इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। रायटर

दूसरी ओर मेदवेदेव ने जापान के विरोध पर सवाल खड़े करते हुए कहा, 'यह द्वीप हमारी जमीन है तो इस यात्रा पर हमें क्यों चिंता होनी चाहिए।' पिछले साल सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना किसी शर्त के 2018 के अंत तक शांति समझौते की बात की थी। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने उनका यह प्रस्ताव खारिज कर दिया था।

अलकायदा के समर्थन वाले तुलसी गबार्ड के आरोप पर भड़के ट्रंप

वाशिंगटन, प्रेट्र : आतंकी संगठन अलकायदा को समर्थन देने के विपक्षी डेमोक्रेट सांसद तुलसी गबार्ड के आरोप पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ट्रंप ने गबार्ड के बयान को हास्यास्पद बताया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ में शामिल गबार्ड ने बीते बुधवार को कहा था कि ट्रंप अलकायदा का समर्थन कर देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवारों की दूसरी बहस में गबार्ड ने यह बात कही थी।

इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आतंकी संगठन और युद्ध के खिलाफ उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा किडेमोक्रेट सांसद तुलसी गबार्ड को नहीं पता कि वह क्या बोल रही हैं। अपने बयान के बचाव में गबार्ड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा सऊदी अरब की मदद करना अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन करना है। बता दें कि गेबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी बने की होड़ में शामिल हैं।

दबाव बनाने को उ. कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट

- आठ दिनों में तीसरी बार किया परीक्षण, वार्ता के लिए प्रयासरत है अमेरिका

सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को फिर से अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया। आठ दिनों में यह उसका तीसरा मिसाइल परीक्षण था। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करके उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव भी बना रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार खत्म कर दे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया इस तरह के परीक्षण कर संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन उनके और उत्तर कोरिया के नेता किम जोग उन के बीच हुआ अनौपचारिक समझौता बरकरार है।

उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की उम्मीद पाले अमेरिकी अधिकारी मिसाइल परीक्षणों पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। वे ट्रंप के साथ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की वार्ता को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह वार्ता वियतनाम की राजधानी हनोई में इसी वर्ष फरवरी में टूट गई थी। 30 जून को ट्रंप ने आगे बढ़कर किम जोंग से फिर संबंध सामान्य बनाने का प्रयास किया। दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान किम जोंग को दोनों देशों के मध्य स्थित असैन्य क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया और खुद उत्तर कोरिया की धरती पर गए। इसलिए अमेरिका मिसाइल परीक्षणों पर कुछ बोलकर ट्रंप-किम जोंग के बीच फिर से वार्ता के बन रहे माहौल को खराब नहीं कर रहा। बैंकॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा है कि कुछ अवरोधों के बावजूद उत्तर कोरिया के साथ हमारी वार्ता आगे बढ़ रही है। पोंपियो यहां आसियान देशों के एक कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। दक्षिण कोरिया ने प्रतिक्रिया में कहा है कि उत्तर कोरिया ने ताजा परीक्षण कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल का किया है। यह 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 220 किलोमीटर की दूरी तक गई। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हमारे खुफिया अधिकारियों की परीक्षण पर नजर है।